एआइ पर जोर

कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक का नया आयाम है- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ). मनुष्य और मशीन की बढ़ती साझेदारी के साथ इस अत्याधुनिक तकनीक को प्रयोगशालाओं से निकालकर रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं. नीति आयोग ने इस संबंध में एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है. रिपोर्टों के अनुसार, इस संस्था ने सरकार के सामने क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और शोध संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है. इसमें शुरुआती तीन सालों में 7,500 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. प्रारूप में पांच क्षेत्रों- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शहरीकरण एवं गतिशीलता- को चिह्नित किया गया है, जिनके लिए एक उच्च स्तरीय कार्य-बल की निगरानी में पांच शोध संस्थाओं और 20 केंद्रों में एआइ तकनीक पर काम होगा. इस योजना पर अगर समुचित रूप से अमल हुआ, तो 2035 तक हमारी अर्थव्यवस्था में 957 अरब डॉलर की राशि जुड़ सकती है तथा वृद्धि दर में 1.3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने का जिम्मा नीति आयोग को दिया था. इसी के अनुरूप पिछले साल जून में यह संस्था एआइ के बारे में एक रणनीतिक मसौदा जारी कर चुकी है. उम्मीद है नयी सरकार जल्दी ही इसे मंजूरी दे देगी, क्योंकि दुनिया के अनेक देश इस तकनीक को अपनाने की होड़ में लगे हैं. चीन ने एआइ के घरेलू उद्योग को स्थापित करने के लिए कुछ सालों में 150 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनायी है. उसका लक्ष्य एक दशक में इस क्षेत्र में अग्रणी होने का है. हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर में इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है. नेशनल बिजनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार, 32 फीसदी से अधिक वित्तीय संस्थाएं एआइ का इस्तेमाल कर रही हैं. इससे सेवा को बेहतर और सुरक्षित बनाने के साथ बैंकिंग के समावेशीकरण में भी मदद मिल रही है. इसी महीने केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एआइ परियोजनाओं पर काम करना अनिवार्य बना दिया है. यह अत्याधुनिक तकनीक के जरिये रक्षा क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है. अर्थिक प्रगति के बावजूद हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि जैसी बड़ी चुनौतियां हैं. इनका सामना करने में एआइ एक कारगर हथियार हो सकता है. ऐसे संकेत हैं कि निजी क्षेत्र भी इसमें निवेश बढ़ाने की ओर अग्रसर है. लेकिन, इससे जुड़े कुछ सवालों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. एआइ, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन जैसे तकनीक रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं. ऐसे में युवाओं को इन तकनीकों के विकास और उपयोग के लिए कौशल एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए. इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा और एआइ उद्यम भी बढ़ेगा. सूचना क्रांति के दौर में भारत ने दुनिया को बेहतरीन विशेषज्ञ और सॉफ्टवेयर मुहैया कराया था. एआइ के क्षेत्र में उस कामयाबी को दोहराने का फिर मौका है.

सूचना क्रांति के दौर में भारत ने दुनिया को बेहतरीन विशेषज्ञ और सॉफ्टवेयर मुहैया कराया था. एआइ के क्षेत्र में उस कामयाबी को दोहराने का फिर मौका है.

प्रकृति बचेगी तो ही हम बचेंगे

ग्रीष्म ऋतु में गर्मी नहीं पड़ेगी तो फिर कब पड़ेगी? पहले भी खूब भीषण गर्मी पड़ी है, बहुत बुरे अकाल की मार पड़ी है. किंतु दो-एक साल के दुष्काल के बाद स्थिति औसत पर लौट आती थी, ऊंच-नीच के बाद सामान्य हालात बहाल हो जाते थे. अब ऐसा नहीं है. हर साल लगने लगा है कि गर्मी और प्रचंड होती जा रही है. शहरों की हालत और भी बुरी है. मौसम विज्ञान की कई रपटें बताती हैं कि आगामी दिनों में इसमें और भी बढ़ोतरी ही होगी.

गर्मी बढ़ने का मामला इतना सीधा नहीं है. उदाहरण के लिए जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो लोग व्यंग्य में पूछते हैं कि जलवायु परिवर्तन का क्या हुआ! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह कई बार कर चुके हैं. ऐसा कहने के पीछे एक बुनियादी चूक होती है. मौसम और जलवायु एक चीज नहीं है. यह अंतर कुछ वैसा ही है जैसा हाथ की घड़ी और पंचांग में होता है. घड़ी हमें एक दिन यानी 24 घंटे के समय का हिसाब दे सकती है, बस, लेकिन पंचांग पूरे साल के बारे में बताता है. मौसम घड़ी की तरह है, जो अल्पकाल में काम करता है. जलवायु पंचांग की तरह होता है, उसका हिसाब मौसमी नहीं होता. मौसम का ठंडा या गर्म होना उतनी गंभीर बात नहीं है, जितनी कि जलवायु परिवर्तन. जलवायु में बदलाव यानी हमारी दुनिया की विराट धुरी का परिवर्तन, यानी साल भर का हिसाब गड़बड़ाना. जब से जलवायु परिवर्तन की जटिलताएं वैज्ञानिकों के सामने धीरे-धीरे उभरी हैं, सालों-साल के शोध के बाद. बहुत पहले से यह समझ आ रहा था कि मौसम का ढर्रा बदलनेवाला है, हमारे ग्रह के ऊपर का औसत तापमान बढ़ने वाला है. जलवायु परिवर्तन की बात वैज्ञानिक बहुत पहले से करते आ रहे हैं और अब जो हो रहा है, यह उनके आंकलन की पुष्टि मात्र है.

औसत तापमान भी एक अलग चीज है. अगर आपके पैर बर्फ में पड़े हों और सर पर आग रख दी गयी हो, तो हो सकता है कि आपके शरीर के बड़े हिस्से का तापमान औसतन ठीक ही हो. लेकिन तब आपका सिर जल जायेगा और पैर ठंड से अकड़ जायेंगे. इसलिए हमें समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से बड़ी समस्या मनुष्य सभ्यता में आज तक आयी ही नहीं है. इसके संदर्भ मनुष्य सभ्यता के कुल इतिहास में नहीं हैं. यह कितनी नयी, विराट और विचित्र चीज है, इसे समझना तो दूर, हमारे लिए इसकी कल्पना भी अत्यंत मुश्किल है.

पहले के जमाने में हमारे उपमहाद्वीप में गांव या शहर बसाते समय हरियाली का ध्यान रखा जाता था. पहले हर गांव-नगर में अमराइयां, वन-उपवन और वाटिकाएं हुआ करती थीं. पहले अमराइयां सिर्फ आम के लिए नहीं लगायी जाती थीं, बल्कि उसकी छांव में तो बरात तक ठहरती थी और वहां लोग इकट्ठा होकर सार्थक संवाद भी किया करते थे. पैड़-पौधे वहां अधिक लगाये जाते थे जहां जल स्रोत हों. राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों में भी हजारों एकड़ के 'ओरण' छोड़े जाते थे. ओरण यानी अरण्य, यानी वन और प्राकृतिक परिवेश. इसी तरह गुजरात के पश्चिमी हिस्सा भी राजस्थान जैसा सूखा क्षेत्र हैं. वहां हमें 'रण' मिलता है, छोटा रण भी और बड़ा भी. रण भी अरण्य का ही अपभ्रंश है. यह दोनों शब्द यही बताते हैं कि हमारे यहां लोग अपनी बस्तियों में प्रकृति के लिए जगह छोड़ते थे, क्योंकि वे मानते थे कि प्रकृति ही मनुष्य को बचा सकती है. अगर हरियाली और पानी के लिए जगह छोड़ेंगे, तो वह हरियाली और पानी हमें पालेगा. आज ऐसा नहीं है. हमारे गांव-शहर हरियाली को केंद्र में रख के नहीं बनाये गये हैं. भीषण गर्मी तो होनी ही है.

सोपान जोशी
पर्यावरणविद्
sopanjoshi@hotmail.com

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदल रहे ढर्रे को लेकर हमारे अंदर थोड़ी विनम्रता की जरूरत है. पहले हम यह मानें कि प्रकृति ने हमें बनाया है. हम प्रकृति के संतुलन से ही बच पायेंगे.

भारत में कुल पानी का लगभग 70-90 प्रतिशत तीन महीने के मॉनसून में गिर जाता है. इस पानी को अगर आप रोक नहीं सकते, तो बाकी समय सूखे की मार निश्चित है. चौमासे के पानी को रोकने के दो ही तरीके हैं- या तो जंगल-पेड़ हों या फिर जलस्रोत हों, संभवतः दोनों हों, क्योंकि पेड़ एवं जलस्रोत एक-दूसरे के बिना आमतौर पर नहीं हो सकते. शहरों में न पेड़ रह गये हैं और न जलस्रोत बचे हैं. ऐसे में यह कैसे संभव है कि शहरों का तापमान न बढ़े?

पहले तालाब बनाना और हरियाली रखना सामाजिक काम था, पुण्य का काम था. आधुनिकता की आंधी में हमने अपने समय-सिद्ध सामाजिक ज्ञान का होम कर दिया. आधुनिकता और विज्ञान से भी उसकी अच्छी-ऊंची बातें नहीं लीं, सिर्फ उसका कचरा ओढ़ लिया है. आज हम परंपरा और आधुनिकता का सिर्फ कचरा ढो रहे हैं, उसकी अच्छाई को हम त्याग चुके हैं. अब हमारे शहर सिर्फ कंक्रीट के होते हैं, जो गर्मी को रोकने की बजाय बढ़ाता है. मौसम के उतार-चढ़ाव के साथ मजबूत बने रहने के हमारे पुराने तरीके चले गये, क्योंकि हमने मान लिया कि आधुनिकता के युग में हम प्रकृति पर विजय कर के उसे अपनी मर्जी के हिसाब से ढाल लेंगे. जलवायु परिवर्तन की बढ़ती मार हम सह नहीं पा रहे हैं. इससे बचने का तरीका बहुत सरल है, कि शहरों में कंक्रीट कम हो और हरियाली बढ़े. लेकिन, यह इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि आज की व्यवस्था में इससे किसी को मुनाफा नहीं है.

हम लोग अपनी घड़ियों में और अपने छोटे काल की समझ में इतने रमे हुए हैं कि हम भूल जाते हैं कि काल का एक बड़ा स्वरूप है, जो पंचांग में निकलकर आता है. यह अगर हम नहीं समझ पाते हैं, तो इसमें बड़ा योगदान पर्यावरण की एक नयी तरह की भोथरी भाषा का भी है. यह भाषा हमारा पढ़ा-लिखा समाज बना रहा है, हमारे नीति-निर्धारक इसे तैयार कर रहे हैं. वे कहते हैं कि हमें पर्यावरण बचाना है, पृथ्वी को बचाना है. जैसे कि पर्यावरण और पृथ्वी हमारे बनाये से बने हैं और हमारे बचाने से बच जायेंगे! असलियत इससे उल्टी है. प्रकृति ने हमको बनाया है, हमने प्रकृति को नहीं बनाया है. अगर हमें कुछ बचाना है, तो अपने आप को ही बचाना होगा, अपने आप ही से. यह रास्ता प्रकृति से निकलेगा. हमें पुरानी व्यवस्थाओं से यह सीखना पड़ेगा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में कैसे मजबूती से बने रहा जा सकता है.

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदल रहे ढर्रे को लेकर हमारे अंदर थोड़ी विनम्रता की जरूरत है. पहले हम यह मानें कि प्रकृति ने हमें बनाया है. हम प्रकृति के संतुलन से ही बच पायेंगे. शहरों में पेड़ काटकर सड़क निर्माण कर देना विकास नहीं, विनाश ही है. विकास के मूल में ही यह अहंकार है कि हम प्रकृति के बनाये नहीं हैं. हमारे अहंकार को तोड़ना प्रकृति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. आज श्रेष्ठ विज्ञान भी हमें उसी विनम्रता का रास्ता दिखा रहा है, जो हमारे सहज सामाजिक व्यवहार में और हमारे अध्यात्म में भी रही है. कोई सुननेवाला है?

(वसीम अकरम से बातचीत पर आधारित)

ट्रेड वार से नयी सरकार को मौका

डॉ जयंतीलाल भंडारी
अर्थशास्त्री
jlbhandari@gmail.com

हम आशा करें कि केंद्र में बननेवाली नयी सरकार भारत को एक ओर ट्रेड वार के खतरों से बचाने तथा दूसरी ओर अमेरिका और चीन में निर्यात बढ़ाने के लिए सुनियोजित रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी.

अमेरिका और चीन के बीच तेजी से बढ़ते ट्रेड वार के खतरों से भारत को बचाना नयी केंद्र सरकार की एक बड़ी चुनौती होगी. एक ओर चीन अपने उन उत्पादों को भारतीय बाजार में तेजी से भेजना चाहेगा, जिन पर अमेरिका में आयात शुल्क बढ़ गया है. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी भारत के उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर भारत को ट्रेड वार की चपेट में ले सकता है. ऐसे में जरूरी होगा कि केंद्र की सरकार भारत को ट्रेड वार के इन नये खतरों से बचाये और अमेरिका तथा चीन में निर्यात बढ़ने की नयी संभावनाओं के मौकों को मुट्ठी में लेने की नयी रणनीति बनाये.

मोजूदा ट्रेड वार को देखते हुए अर्थ-विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि यद्यपि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका और चीन में भारत से निर्यात बढ़ने की संभावनाओं के नये मौके भी निर्मित होंगे. वैश्विक स्तर पर यह अध्ययन रिपोर्ट पेश हुई है कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 में अमेरिका-चीन के ट्रेड वार के कारण इन दोनों देशों में भारत से 3.5 फीसदी निर्यात बढ़ेंगे. दरअसल, अमेरिका ने पिछले वर्ष जनवरी में चीन के कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क लगातार व्यापार युद्ध की शुरुआत की. इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगा दिये. धीरे-धीरे ये दोनों देश एक-दूसरे से आयात होनेवाली कई वस्तुओं पर आयात शुल्क आरोपित करते गये. भारी हानि की आशंका को देखते हुए अमेरिका और चीन ने 24 अगस्त, 2018 के बाद लगातार समाधान वार्ता आयोजित की. लेकिन, 10 मई तक इस वार्ता का कोई समाधान नहीं निकला और अमेरिका ने 10 मई से चीन से आयातित 200 अरब डॉलर की वस्तुओं पर शुल्क की दर मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी. इस पर 13 मई को चीन ने कहा कि वह 1 जून से अमेरिका से आयात होनेवाले 60 अरब डॉलर मूल्य की 5,140 वस्तुओं पर आयात शुल्क पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 25 फीसदी कर देगा.

यद्यपि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन भारत के लिए इन दोनों देशों में निर्यात बढ़ाने के जो मौके निर्मित हुए हैं. इससे देश का व्यापार घाटा कम करने में भी मदद मिलेगी. विदेश व्यापार विशेषज्ञों का मत है कि अमेरिका से चीन में अमेरिकी सामानों की आवक घटने पर भारत अब चीन को करीब सौ उत्पादों की आपूर्ति बड़े पैमाने पर कर सकता है. इनमें तंबाकू, ताजा अंगूर, रबर, गोंद, ल्युब्रिकेंट्स, सोयाबीन, ऑयल, स्टील, कॉटन, बादाम, अखरोट, कृषि उत्पाद, विभिन्न रसायन आदि शामिल हैं. भारत संतरे, बादाम, अखरोट, गेहूं और मक्का का निर्यात दूसरे देशों को तो करता है, लेकिन चीन को नहीं करता. चीन इन चीजों को अमेरिका से खरीदता है. अप्रैल 2019 में चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार में व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत ने 380 उत्पादों की सूची चीन को भेजी थी, जिनका चीन को निर्यात बढ़ाया जा सकता है. इनमें मुख्य रूप से बागवानी, वस्त्र, रसायन और औषधि क्षेत्र के उत्पाद शामिल हैं.

वर्तमान में चीन भारतीय उत्पादों का तीसरा बड़ा निर्यात बाजार है. वहीं चीन से भारत सबसे ज्यादा आयात करता है. दोनों देशों के बीच 2001-02 में आपसी व्यापार तीन अरब डॉलर था, जो 2018-19 में बढ़कर करीब 88 अरब डॉलर पर पहुंच गया. पिछले वर्ष भारत से चीन को निर्यात बढ़कर 18 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो वर्ष 2017-18 में 13 अरब डॉलर था. इतना ही नहीं चीन से भारत का आयात भी 75 अरब डॉलर से कम होकर 70 अरब डॉलर रह गया. ऐसे में अमेरिका और चीन के ट्रेड वार के बीच भारत से चीन को निर्यात बढ़ने की संभावनाओं से भारत-चीन व्यापार घाटे में और कमी आयेगी.

ट्रेड वार के मोर्चे पर अमेरिका का सामना करने के लिए और भारत को अपने पक्ष में करने के लिए चीन करीब आता दिख रहा है. इसी तरह अमेरिका में चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क संबंधी प्रतिबंधों के कारण अमेरिका में चीनी उत्पादों की आमद घट जायेगी. ऐसे में भारत अमेरिका में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन, परिवहन कल पुर्जे, रसायन, प्लास्टिक, रबड़ जैसे उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात बढ़ा सकता है. भारत अमेरिका को टेक्सटाइल, गारमेंट और जेम्स-ज्वैलरी का निर्यात भी बढ़ा सकता है. अमेरिका के लिए मेक्सिको के बाद चीन ऑटो पार्ट्स का दूसरा बड़ा सप्लायर है. कुछ अमेरिकी कंपनियां भारत से इन्हें खरीदने में रुचि दिखा रही हैं. यद्यपि अमेरिका को भारत के निर्यात की नयी संभावनाएं हैं, लेकिन यह जरूरी है कि भारत के अमेरिका के साथ व्यापार मतभेदों का उपयुक्त समाधान हो.

भारत का यह एक सराहनीय कदम है कि अमेरिका से आयातित, बादाम, अखरोट और दालें समेत 29 वस्तुओं पर भारत ने जवाबी शुल्क लगाने की समय-सीमा को लगातार आगे बढ़ाया है और अब यह सीमा 16 जून, 2019 तक है. ऐसे में भारत-अमेरिका के बीच कारोबारी तनाव को कम करने के लिए व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाना होगा. ऐसा होने पर ही अमेरिका-चीन के ट्रेड वार का फायदा लेते हुए भारत अमेरिका को निर्यात में नये सिरे से वृद्धि कर सकेगा. हम आशा करें कि केंद्र में बननेवाली नयी सरकार भारत को एक ओर ट्रेड वार के खतरों से बचाने तथा दूसरी ओर अमेरिका और चीन में निर्यात बढ़ाने के लिए सुनियोजित रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी.

बोधि वृक्ष

हंसी का अर्थ

बहुत लंबे समय से लोग कह रहे हैं कि हंसी सबसे अच्छी दवा है. कहीं पर कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि खुश, आनंदमय रहनेवाले लोग अपने आप को स्वाभाविक रूप से ठीक कर लेते हैं. आप स्वस्थ हैं या बीमार, यह बस इस से तय होता है कि आप का शरीर कितने अच्छे से काम कर रहा है. अगर ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो हम इसे अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं. अगर ऐसा नहीं हो तो हम इसे बीमारी कहते हैं. जब आप खुश हैं, आनंदपूर्ण हैं, तब आप का भौतिक शरीर सबसे अच्छे तरीके से काम करता है. तब इसके लिए ठीक रहना, स्वस्थ रहना स्वाभाविक ही है. हंसी आप को ठीक नहीं करती, वह तो अंदर की खुशी है, जो ये करती है, लेकिन लोगों ने हंसी को आनंद के साथ बहुत ज्यादा जोड़ दिया है. गौतम कभी जोर से नहीं हंसते थे, स्पष्ट रूप से मुस्कुराते भी नहीं थे, उनकी मुस्कुराहट भी हल्की सी, छोटी सी होती थी. हंसी एक बंधन भी बन सकती है. अगर आप को यह विश्वास है कि खुशी, आनंद का अर्थ हमेशा 'हा हा हा' करना है, तो आप अपने आप में हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण होंगे, क्योंकि सभी प्रकार की परिस्थितियों में, बिना परिस्थिति की गहराई और उसके आयामों को समझे, आप 'हा हा हा' करते रहेंगे. आनंद का अर्थ हंसी नहीं है. आनंद की अभिव्यक्ति हरसंभव प्रकार से हो सकती है- ये जरूरी नहीं है कि ये किसी एक खास तरह से ही व्यक्त हो. ये हंसी के रूप में व्यक्त हो सकता है, ये मौन के रूप में भी व्यक्त हो सकता है. आनंद आप में स्थिरता ला सकता है, आपको कामों में लगा सकता है, या इससे आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं. आनंद का अर्थ हंसी या मुस्कुराहट नहीं है. आनंद का अर्थ है कि आप जीवन के मूल पर स्थित हैं. जिस क्षण आप इसे किसी एक खास अभिव्यक्ति या प्रकट करने के तरीके का गुलाम बना देते हैं, आप यह सुनिश्चित कर देते हैं कि आप हर समय आनंद में नहीं रह पायेंगे. आनंद का अर्थ यह है कि मूल रूप से आप जीवन की गहराई तक पहुंच चुके हैं, आप जीवन की सतह पर नहीं हैं.

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

आपके पत्र

ट्रंप पर महाभियोग की मांग

अब तक बाहर वाले ही राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग कब से कर रहे थे, अब तो उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के मिशिगन से सांसद जस्टिन अमाश ने भी महाभियोग चलाने की मांग कर दी है. क्या ऐसा होगा? अमेरिकी इतिहास में ट्रंप तीसरे राष्ट्रपति होंगे, जिनके विरुद्ध इस तरह की प्रक्रिया अपनायी जायेगी. वर्ष 1868 में एंड्रू जॉनसन के खिलाफ महाभियोग चला था. फिर 1998 में बिल क्लिंटन पर भी महाभियोग लगा था, जिसमें उनकी जीत हुई थी. 1974 में रिचर्ड निक्सन पर भी इम्पीचमेंट चलाने की बात शुरू ही हुई थी, पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था. पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रुसी दखलंदाजी पर रॉबर्ट म्युलर ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उस पर विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि उस रिपोर्ट का निचोड़ था कि रूस ने किसी तरह का हस्तक्षेप चुनावों में नहीं किया है, मगर जब पिछले दिनों विदेश मंत्री माइक पोम्पियो रूस के दौरे पर गये थे, तो उन्होंने रूसी अधिकारियों से कहा था कि अमेरिकी चुनावों में वह हस्तक्षेप नहीं करे. इसका मतलब क्या हुआ? एक ओर रिपोर्ट में रूस को क्लीनचिट दी जाती है, वहीं दूसरी ओर उसे हिदायत दी जा रही है!

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

बंपर वोटिंग का संदेश

लोकसभा चुनाव, 2019 के अंतिम चरण में संताल परगना की तीन सीटों के लिए हुए चुनाव में बंपर वोटिंग हुई. निश्चय ही सरकार एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाये गये मतदाता जागरूकता अभियान का यह प्रभाव है. इससे साफ तौर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है. नतीजतन, वर्ष 2014 की तुलना में इस बार की वोटिंग में प्रायः तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी. चिलचिलाती धूप में भी मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है. लिहाजा, निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी को भी मतदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व का ईमानदारी से पालन करना होगा, उनके सुख-दुख में खड़ा रहना होगा. इलाके के विकास के लिए आगे बढ़ना होगा.

शंभु सहाय, बिलासी, देवघर

अफवाह फैलाने से बचें

अभी-अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है और लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ अपना कीमती वोट अपने मनपसंद उम्मीदवार को दिया, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगी, वह यह है कि कुछ लोगों की शरारत के कारण दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. वह महज अफवाह थी कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वे भी आधार कार्ड और दो फोटो की मदद से वोट डाल सकते हैं. इस अफवाह को हजारों लोगों ने बिना सत्यापन और बिना कुछ सोचे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया. नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को नाहक परेशान होना पड़ा और मतदान केंद्रों से निराश होकर लौटना पड़ा, जिन्होंने इस तरह के पोस्ट पर जरा भी भरोसा किया. मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी अफवाह आप न फैलाएं और न ही ऐसा करने में भागीदार बनें.

अंकित वर्णवाल, इमेल से.

कुछ अलग

जहां विस्मय तरबूज की तरह

सुधांशु फिरदौस
साहित्यकार
sudhansufirdaus@gmail.com

जेठ की तपती दोपहर में जब हम लू की लहर से बचने के लिए तरबूज की ओर शीतलता की उम्मीद से देखते हैं, तब इसी धूप में नदी की रेत के खेत में तपते तरबूज किसानों का जलता हुआ खून-पसीना हमसे नजरअंदाज हो जाता है. जिस तरबूज को खरीदने में हमारी आंख निकलती है, उसके लिए किसानों को पैकारों से बहुत ही न्यूनतम मूल्य मिलता है. आलोक धन्वा की काव्य पंक्ति 'जहां विस्मय/तरबूज की तरह/जितना हरा उतना ही लाल' और किसी के लिए पता नहीं क्या मानी रखता है, लेकिन गंडक के तटीय इलाकों में तरबूज के किसानों की स्थिति बताने के लिए यह पंक्ति मानीखेज है. यहां ज्यादातर किसानों का जीवन असुरक्षा से घिरा हुआ है. यह असुरक्षा तरबूज की खेती में लगनेवाले अत्यधिक खर्च और फसल तैयार होने पर इस रकम वापसी की अनिश्चितता के कारण है. ज्यादातर किसान महंगी दर से जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हैं, जिसका उनके पास कोई दस्तावेज भी नहीं है कि वह फसल बीमा मिलने जैसी स्थिति में किसी को बता सकें कि मेरी इतने बीघे की खेती है. बीज से खाद तक सब कुछ इन्हें बहुत महंगा मिलता है. सरकार से कोई भी मदद या सहूलियत नहीं मिलती. बहुसंख्य किसान ब्याज पर पैसे लेकर खेती करते हैं, जिससे कर्ज चुकाने का अतरिक्त दबाव होता है.

सरकार या किसी एजेंसी से कोई भी फसल बीमा तरबूज किसानों को उपलब्ध नहीं है. कुछ लोगों को मुनाफा होता है, लेकिन ज्यादातर किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती है. कभी-कभी कर्ज न चुकाना इतना दारुण हो जाता है कि आत्महत्या जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है. ज्यादातर किसान इस खेती को जुआ मानते हैं. उन्हें फसल बर्बाद होने का खतरा तो है, लेकिन बालू में वे करें भी क्या?

अफसोस की बात यह है कि सरकार की तरफ से एक रत्ती भर भी सहयोग नहीं मिलता है. वे लोग अपने ही दम पर मिट्टी को सोना बनाने का जुआ खेलते हैं. कुछ डूब जाते हैं, तो कुछ पार होते हैं. नदी उनसे फसल छीनती है, तो यही नदी अगली बार फसल देती भी है. वे नदी से कभी भी नाउम्मीद नहीं होते. सरकार तरबूज को लेकर कितना उदासीन है, इसका एहसास तरबूज उत्पादन के आंकड़ों को देखकर होता है. पूरे देश में तरबूज उत्पादन की अनुकूल स्थिति होने के बावजूद भारत विश्व उत्पादन में मात्र 0.38 प्रतिशत ही योगदान कर पाता है, जबकि बिहार पूरे देश के तरबूज उत्पादन का मात्र 1.28 प्रतिशत ही उपजा पाता है. वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पूरे देश का एक चौथाई से अधिक तरबूज अकेले उपजाता है.

तरबूज की खेती को लेकर इस इलाके में अपार संभावना है. सरकारी महकमा इन किसानों को लेकर लापरवाह है. असमय वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे गंडक का जलस्तर बढ़ जाता है, तरबूज की हजारों एकड़ फसल डूब जाती है और हजारों घरों की उम्मीद भी. लेकिन, यहां प्रशासन का कोई नुमाइंदा या कोई जनप्रतिनिधि इन किसानों की खोज-खबर लेने भी नहीं आता!

देश दुनिया से

ईयू में जगह बनाने की ग्रीस की कोशिश

ग्रीस (यूनान) यूं तो यूरोप की कुल आबादी का सिर्फ दो प्रतिशत से कुछ ज्यादा है, लेकिन पिछले सालों में आर्थिक मुश्किलों की वजह से वह यूरोप के सबसे अहम मुद्दों में शामिल रहा है. अब वह यूरोपीय संघ (ईयू) में जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ है. ग्रीस के आर्थिक संकट और 2015 के शरणार्थी संकट ने आज के यूरोप को बहुत हद तक परिभाषित किया है. यूरोप के दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित ग्रीस भारत की ही तरह लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जहां सरकार का मुखिया संसद में बहुमत का नेता प्रधानमंत्री होता है. राज्य प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो मुख्य रूप से देश का प्रतिनिधित्व करता है. ग्रीस में औपचारिक रूप से मतदान अनिवार्य है, लेकिन इसकी हकीकत में जांच नहीं की जाती. संसद में 300 सीटें हैं. चुनाव 59 चुनाव क्षेत्रों में होता है. अठारह साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है. इस साल अक्तूबर में होनेवाले संसदीय चुनावों से मतदान की उम्र घटाकर 17 वर्ष की जा रही है. यूरोपीय संसद में ग्रीस 21 सदस्य भेजता है. वह 1981 से यूरोपीय संघ का सदस्य है और 2000 से शेंगेन का और 2001 से यूरो जोन का सदस्य है. ग्रीस पुराने यूरोपीय संघ के गरीब देशों में शामिल है.

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है